



Lakshya IAS

academy

20

Sep 2026

DAILY CURRENT AFFAIRS



Mr. R.P. Singh Sir
(MD)



1. प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तीन वर्ष पूरे, योजना के तहत ३० लाख पारंपरिक कारीगर पंजीकृत

- ✎ प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, जिसे १७ सितंबर २०२३ को शुरू किया गया था, ने १८ पारंपरिक व्यवसायों में ३० लाख कारीगरों के पंजीकरण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय को नोडल मंत्रालय के रूप में लागू की जा रही यह पहल पहचान, कौशल प्रशिक्षण, औजार किट, बिना किसी जमानत के ऋण और बाजार से जुड़ाव सहित समग्र सहायता प्रदान करती है। लगभग २४.५० लाख लाभार्थियों ने बुनियादी कौशल प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जिससे पारंपरिक कामगारों को औपचारिक उद्यमिता व्यवस्था से जुड़ने में सहायता मिली है।



PM Vishwakarma Marks Three Years with 30 Lakh Traditional Artisans Registered Under the Scheme

- ✎ The PM Vishwakarma scheme, launched on 17th September 2023, reached its target of registering 30 lakh artisans across 18 traditional trades. Implemented by the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises as the nodal agency, the initiative offers end-to-end support including recognition, skill training, toolkits, collateral-free credit, and market integration. Around 24.50 lakh beneficiaries received basic skill training, helping shift traditional workers into formal enterprise ecosystems.



मुख्य बिंदु:

- पंजीकरण लक्ष्य प्राप्त: प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना ने योजना के तहत निर्धारित तीन चरणों वाली सत्यापन प्रक्रिया पूरी करने के बाद ३० लाख पारंपरिक कारीगरों का पंजीकरण किया है।
- पारंपरिक व्यवसायों में सहायता: यह योजना १८ पारंपरिक व्यवसायों को शामिल करती है और पहचान, कौशल प्रशिक्षण, औजार प्रोत्साहन, ऋण सहायता, डिजिटल लेनदेन प्रोत्साहन और विपणन सहायता प्रदान करती है।
- कौशल और बाजार तक पहुंच: लगभग २४.५० लाख पंजीकृत लाभार्थियों ने बुनियादी कौशल प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जबकि कारीगरों को व्यापक बाजारों से जोड़ा जा रहा है।

Key Points:

- Registration Target Achieved: PM Vishwakarma has registered 30 lakh traditional artisans after completing the prescribed three-stage verification process under the scheme.
- Support Across Traditional Trades: The scheme covers 18 traditional trades, offering recognition, skill training, toolkit incentives, credit support, digital transaction incentives and marketing assistance.
- Skills And Market Access: Around 24.50 lakh registered beneficiaries have received basic skill training, while artisans are being connected with wider markets.

2. नई आयात शर्तों के तहत सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए चीनी भंडारण सीमा को दोगुना कर ३० दिन किया

केंद्र सरकार ने अधिक मांग वाले समय में परिचालन संबंधी लचीलापन प्रदान करने के लिए थोक उपभोक्ताओं के लिए अनुमत चीनी भंडारण सीमा को १५ दिनों से बढ़ाकर ३० दिन कर दिया है। संशोधित दिशानिर्देशों के तहत, प्रारंभिक १५ दिनों की सीमा से अधिक रखा गया कोई भी भंडार निर्धारित प्राधिकरण व्यवस्था के तहत किए गए आयात से ही प्राप्त किया जाना चाहिए। घरेलू खुले बाजार से खरीदी गई चीनी का भंडारण अभी भी मूल १५ दिनों की सीमा तक ही सीमित है। इसके अतिरिक्त, प्रति माह १० मीट्रिक टन से अधिक चीनी का उपयोग करने वाली संस्थाओं को प्रत्येक शुक्रवार को अनिवार्य साप्ताहिक भंडार विवरण प्रस्तुत करना होगा।



मुख्य बिंदु:

- भंडारण सीमा में वृद्धि: सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए अनुमत चीनी भंडारण अवधि को १५ दिनों से बढ़ाकर ३० दिन कर दिया है।
- आयातित चीनी की आवश्यकता: मौजूदा १५ दिनों की सीमा से अधिक रखा गया भंडार निर्दिष्ट प्राधिकरण योजनाओं के तहत आयात की गई चीनी से प्राप्त होना चाहिए।
- साप्ताहिक भंडार विवरण: प्रति माह १० मीट्रिक टन से अधिक चीनी का उपयोग करने वाले थोक उपभोक्ताओं को प्रत्येक शुक्रवार को निर्धारित पोर्टल के माध्यम से अपने चीनी भंडार का विवरण देना होगा।

3. ताजिकिस्तान में एससीओ के आर्थिक और विदेश व्यापार मंत्रियों की २५वीं बैठक आयोजित

शंघाई सहयोग संगठन के आर्थिक और विदेश व्यापार मंत्रियों की २५वीं बैठक ताजिकिस्तान के दुशांबे में आयोजित हुई, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय व्यापार और आर्थिक समन्वय को गहरा करना था।



भारत ने व्यापार लागत कम करने, बहुविध परिवहन संपर्क बढ़ाने और प्रमुख क्षेत्रों में मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के निर्माण पर जोर दिया। सदस्य देशों ने बहुपक्षीय आर्थिक सहयोग के लिए २०२६ से २०३० की कार्ययोजना को अंतिम रूप दिया और रचनात्मक अर्थव्यवस्था के विकास के लिए रूपरेखाओं को मंजूरी दी। इसके अतिरिक्त, प्रतिनिधियों ने क्षेत्रीय व्यापार बाधाओं को कम करने, डिजिटल भुगतान के एकीकरण और कागजरहित सीमा शुल्क पहलों की समीक्षा की।

Government Doubles Sugar Stockholding Limit for Bulk Consumers to 30 Days Under New Import Conditions

The central government doubled the permissible sugar stockholding limit for bulk consumers from fifteen days to thirty days to provide operational flexibility during peak demand. Under the updated guidelines, any stock retained past the initial fifteen-day threshold must be sourced exclusively from imports under designated authorization frameworks. Stock purchased from domestic open markets remains restricted to the original fifteen-day limit. Additionally, entities utilizing over ten metric tonnes monthly must submit mandatory weekly stock declarations every Friday.



Key Points:

- Stock Limit Increased: The government has raised the permissible sugar stockholding period for bulk consumers from 15 days to 30 days.
- Imported Sugar Requirement: Stocks held beyond the existing 15-day limit must be sourced from sugar imported under specified authorisation schemes.
- Weekly Stock Disclosure: Bulk consumers using more than 10 metric tonnes monthly must disclose their sugar stocks every Friday through the designated portal.

3. SCO Economic and Foreign Trade Ministers Convene for 25th Meeting in Tajikistan

The 25th Shanghai Cooperation Organisation Economic and Foreign Trade Ministers meeting convened in Dushanbe, Tajikistan, to deepen regional trade and economic alignment. India emphasized lowering trade costs, enhancing multimodal connectivity, and building resilient supply chains across key sectors. Member nations finalized the 2026 to 2030 Action Plan for multilateral economic cooperation and approved frameworks for developing a creative economy. Additionally, representatives reviewed regional trade barrier reductions, digital payment integration, and paperless customs initiatives.



मुख्य बिंदु:

- दुशांबे में बैठक: विदेश आर्थिक और विदेश व्यापार गतिविधियों के लिए जिम्मेदार मंत्रियों की एससीओ की २५वीं बैठक दुशांबे में आयोजित हुई।
- व्यापार सहयोग पर चर्चा: मंत्रियों ने आपसी व्यापार, व्यापार बाधाओं को कम करने, प्रक्रियाओं में सुधार, संपर्क व्यवस्था को मजबूत करने और उत्पादन तथा व्यापार श्रृंखलाओं की मजबूती बढ़ाने पर चर्चा की।
- कार्ययोजना पर सहमति: प्रतिभागियों ने एससीओ बहुपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम को लागू करने के लिए २०२६-२०३० की कार्ययोजना पर सहमति व्यक्त की।

4. भारत और नेपाल ने अनधिकृत व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए नई दिल्ली में अंतर-सरकारी वार्ता आयोजित की

- ✗ अनधिकृत व्यापार को नियंत्रित करने के लिए व्यापार, पारगमन और सहयोग पर भारत-नेपाल अंतर-सरकारी उप-समिति की बैठक नई दिल्ली के वाणिज्य भवन में आयोजित हुई। दोनों देशों के संयुक्त सचिव स्तर के प्रतिनिधि मंडलों ने कृषि, डेयरी, औषधि और आयुष वस्तुओं के लिए बाजार पहुंच के विस्तार सहित प्रमुख व्यापारिक पहलुओं का मूल्यांकन किया। चर्चाओं में सीमा अवसंरचना, एकीकृत जांच चौकियों, सीमा शुल्क स्वचालन और आगमन-पूर्व आंकड़ों के आदान-प्रदान पर ध्यान केंद्रित किया गया। दोनों पक्षों ने १९५० की संधि के तहत वैध पारगमन मार्गों को सुगम बनाते हुए अवैध सीमा-पार वाणिज्यिक धोखाधड़ी को रोकने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।



मुख्य बिंदु:

- द्विपक्षीय समिति की बैठक: भारत-नेपाल अंतर-सरकारी उप-समिति की बैठक १६ और १७ सितंबर को नई दिल्ली में व्यापार संबंधी मुद्दों की समीक्षा के लिए हुई।
- व्यापार और पारगमन की समीक्षा: चर्चाओं में द्विपक्षीय व्यापार, पारगमन व्यवस्था और सहयोग तंत्र को शामिल किया गया, जिसमें वैध वाणिज्यिक आवागमन को सुगम बनाने पर जोर दिया गया।
- अनधिकृत व्यापार पर चर्चा: यह संस्थागत तंत्र अनधिकृत व्यापार से संबंधित मुद्दों की विशेष रूप से समीक्षा करता है और सुगम द्विपक्षीय व्यापार तथा पारगमन का समर्थन करता है।

Key Points:

- Dushanbe Meeting Held: The 25th SCO meeting of ministers responsible for foreign economic and foreign trade activities was held in Dushanbe.
- Trade Cooperation Discussed: Ministers discussed mutual trade, reducing trade barriers, improving procedures, strengthening connectivity and enhancing production and trade chain resilience.
- Action Plan Agreed: Participants agreed on a 2026-2030 action plan for implementing the SCO multilateral trade and economic cooperation programme.

4. India and Nepal Hold Inter-Governmental Talks in New Delhi to Curb Unauthorised Trade

- ✗ The India-Nepal Inter-Governmental Sub-Committee on Trade, Transit, and Cooperation to Control Unauthorised Trade convened at Vanijya Bhawan, New Delhi. Joint Secretary level delegations from both nations evaluated key trade parameters, including expanded market access for agricultural, dairy, pharmaceutical, and AYUSH items. Discussions targeted border infrastructure, integrated check posts, customs automation, and pre-arrival data exchanges. Both sides committed to suppressing illegal cross-border commercial fraud while streamlining valid transit routes under the 1950 Treaty framework.



Key Points:

- Bilateral Committee Meets: The India-Nepal Inter-Governmental Sub-Committee met in New Delhi on September 16 and 17 to examine trade-related issues.
- Trade And Transit Reviewed: Discussions covered bilateral trade, transit arrangements and cooperation mechanisms, with emphasis on facilitating legitimate commercial movement.
- Unauthorised Trade Addressed: The institutional mechanism specifically examines issues related to unauthorised trade while supporting smoother bilateral trade and transit.

5. कोचीन शिपयार्ड में दूसरी मिसाइल पोत के लिए इस्पात काटने के साथ भारतीय नौसेना ने अगली पीढ़ी के मिसाइल पोत कार्यक्रम में प्रगति की



- कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने १७ सितंबर २०२६ को कोच्चि में दूसरी अगली पीढ़ी

की मिसाइल पोत के लिए इस्पात काटने का समारोह आयोजित किया। मार्च २०२३ में छह उच्च गति वाले युद्धपोतों के निर्माण के लिए हस्ताक्षरित अनुबंध के तहत, इन पोतों में उन्नत गुप्त प्रणालियां, पोत-रोधी मिसाइलें और बिंदु-रक्षा प्रौद्योगिकी शामिल होगी, जिससे हिंद महासागर क्षेत्र में परिचालन सुरक्षा को मजबूत किया जा सकेगा। स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए भूमिका-निर्धारक उपकरणों से सुसज्जित यह परियोजना आधुनिक और युद्ध के लिए तैयार नौसैनिक बल के निर्माण के राष्ट्रीय रक्षा विनिर्माण लक्ष्यों के अनुरूप है।

मुख्य बिंदु:

- दूसरी पोत का निर्माण शुरू: कोच्चि में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में दूसरी अगली पीढ़ी की मिसाइल पोत के लिए इस्पात काटने का कार्य किया गया।
- उन्नत हथियार और सेंसर: इन पोतों में आधुनिक हथियार प्रणालियों और सेंसरों को शामिल करने की योजना है, जिससे भारतीय नौसेना की परिचालन क्षमताओं को मजबूत किया जा सके।
- स्वदेशी उपकरणों पर जोर: प्रमुख भूमिका-निर्धारक उपकरणों का स्वदेशी रूप से विकास और निर्माण किया गया है, जिससे घरेलू रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलता है।

5. Indian Navy Advances NGMV Programme as Cochin Shipyard Begins Steel Cutting of Second Missile Vessel



- Cochin Shipyard Limited held the steel-cutting ceremony for the second Next Generation Missile Vessel on seventeen September 2026 in Kochi. Under the contract signed in March 2023 for six high-speed warship units, these vessels will feature advanced stealth systems, anti-ship missiles, and point-defence technology to bolster operational security in the Indian Ocean Region. Equipped with indigenously designed role-defining hardware, the project aligns with national defense manufacturing goals to build a modern, combat-ready naval force.

Key Points:

- **Second Vessel Construction Begins:** Steel cutting for the second Next Generation Missile Vessel was conducted at Cochin Shipyard Limited in Kochi.
- **Advanced Weapons And Sensors:** The vessels are planned to feature modern weapon systems and sensors, strengthening the Indian Navy's operational capabilities.
- **Indigenous Equipment Focus:** Major role-defining equipment has been indigenously developed and manufactured, supporting domestic defence production and self-reliance.

6. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने अवांछित वाणिज्यिक संचार पर रोक लगाने और उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी आधारित उपायों का विस्तार किया

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने दूरसंचार नेटवर्क में अवांछित वाणिज्यिक संचार पर रोक लगाने के लिए प्रवर्तन तंत्र को मजबूत किया है। इस



व्यवस्था के तहत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को संदिग्ध प्रेषकों का पता लगाने, अवांछित संदेशों के स्वरूप का विश्लेषण करने और अनधिकृत संचार के स्रोतों का पता लगाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाधानों सहित उन्नत प्रौद्योगिकी मंचों को लागू करना होगा। उपभोक्ता १९०९ हेल्पलाइन, विशेष मोबाइल अनुप्रयोगों या आधिकारिक नियामक पोर्टलों के माध्यम से उल्लंघनों की सक्रिय रूप से शिकायत कर सकते हैं। इन व्यापक उपायों का उद्देश्य मोबाइल उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा करना, डिजिटल सुरक्षा बढ़ाना, शिकायत निवारण को सुव्यवस्थित करना और वाणिज्यिक संस्थाओं की जवाबदेही सुनिश्चित करना है।

मुख्य बिंदु:

- प्रौद्योगिकी आधारित प्रवर्तन: भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने प्रौद्योगिकी आधारित प्रवर्तन और उन्नत उपभोक्ता सुरक्षा उपायों के माध्यम से अवांछित वाणिज्यिक संचार को नियंत्रित करने के लिए अपनी व्यवस्था को मजबूत किया है।
- अवांछित संदेशों का पता लगाने में सुधार: दूरसंचार प्रदाताओं को संदिग्ध प्रेषकों का पता लगाने, शिकायतों का विश्लेषण करने और अवांछित संचार के स्रोतों की पहचान करने के लिए तकनीकी प्रणालियों का उपयोग करना आवश्यक है।
- उपभोक्ता शिकायतों को समर्थन: उपभोक्ता १९०९ सेवा और अवांछित संचार निवारण अनुप्रयोग सहित निर्धारित माध्यमों के जरिए अवांछित वाणिज्यिक संचार की शिकायत कर सकते हैं।

TRAI Expands Technology-Based Measures to Curb Unsolicited Commercial Communications and Protect Consumers

The Telecom Regulatory Authority of India strengthened enforcement mechanisms to curb unsolicited commercial communications across telecommunication networks. Under this framework, telecom service providers must deploy advanced technology platforms, including artificial intelligence solutions, to detect suspicious senders, analyze spam patterns, and track unauthorized communication sources. Consumers can actively report violations through the 1909 helpline, specialized mobile applications, or official regulatory portals. These comprehensive measures aim to protect mobile users, enhance digital security, streamline complaint redressal, and enforce accountability among commercial entities.



Key Points:

- Technology Driven Enforcement: TRAI has strengthened its framework for controlling unsolicited commercial communications through technology-driven enforcement and enhanced consumer protection measures.
- Spam Detection Enhanced: Telecom providers are required to use technical systems for detecting suspicious senders, analysing complaints and identifying sources of unwanted communications.
- Consumer Complaints Supported: Consumers can report unsolicited commercial communications through designated channels, including the 1909 service and DND application.

7. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने भारत के चयनित जिलों को शामिल करते हुए श्रम बाजार की स्थिति का विवरण जारी किया

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने उप-राज्य सांख्यिकीय ढांचे को मजबूत करने के लिए जिला-स्तरीय आर्थिक अनुमान जारी किए। बड़े पैमाने पर किए गए उद्यम सर्वेक्षणों से प्राप्त ये विस्तृत आंकड़े परिचालन संबंधी मापदंडों, सकल मूल्य वर्धन और रोजगार वितरण का विश्लेषण करते हैं। निष्कर्षों से पता चलता है कि ५० शीर्ष प्रदर्शन करने वाले जिले कुल क्षेत्रीय उत्पादन और कार्यबल भागीदारी का लगभग एक-तिहाई हिस्सा उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा, २३७ जिलों में महिला कामगार कुल असंगठित कार्यबल का कम से कम एक-तिहाई हिस्सा हैं, जो स्थानीय रोजगार रणनीतियां तैयार करने के लिए उपयोगी आंकड़े उपलब्ध कराते हैं।



मुख्य बिंदु:

- जिला श्रम आंकड़े: यह विवरण चयनित जिलों को शामिल करते हुए श्रम बाजार संबंधी जानकारी प्रदान करता है और भारत के रोजगार सांख्यिकी ढांचे में भौगोलिक रूप से विस्तृत आंकड़े जोड़ता है।
- रोजगार संकेतक प्रस्तुत: जिला-स्तरीय संकेतक देश के विभिन्न हिस्सों में श्रम भागीदारी, रोजगार की स्थितियों और कार्यबल की विशेषताओं का अध्ययन करने में सहायता करते हैं।
- नीतिगत साक्ष्य मजबूत: जिला-केंद्रित आंकड़े स्थानीय श्रम बाजारों के अधिक लक्षित मूल्यांकन में सहायता कर सकते हैं और साक्ष्य-आधारित रोजगार नीति नियोजन में उपयोगी हो सकते हैं।

8. पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा १९ सितंबर को किया जाएगा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी १९ सितंबर २०२६ को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में "पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य" नामक दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में १७ देशों के प्रतिनिधि, न्यायाधीश और विशेषज्ञ जलवायु चुनौतियों, नीतिगत क्रियान्वयन और पर्यावरणीय न्याय का अध्ययन करने के लिए एकत्र होंगे। सत्रों में बहु-क्षेत्राधिकार सहयोग को आगे बढ़ाने, कानूनी तरीकों के आदान-प्रदान और शासन रणनीतियों तथा जलवायु लचीलेपन को लागू करने के लिए संस्थागत ढांचे को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।



7. MoSPI Releases Labour Market Snapshot Covering Selected Districts Across India

The Ministry of Statistics and Programme Implementation released district-level economic estimates to strengthen sub-state statistical frameworks. Derived from large-scale enterprise surveys, these granular figures analyze operational parameters, gross value added, and employment distribution. Findings indicate that fifty top-performing districts generate nearly one-third of overall sector output and workforce participation. Furthermore, female workers comprise at least one-third of the total unincorporated workforce across two hundred thirty-seven districts, offering actionable data to formulate localized employment strategies.



Key Points:

- District Labour Data: The snapshot provides labour market information covering selected districts, adding geographically detailed evidence to India's employment statistics framework.
- Employment Indicators Presented: District-level indicators help examine labour participation, employment conditions and workforce characteristics across different parts of the country.
- Policy Evidence Strengthened: The district-focused statistics can support more targeted assessment of local labour markets and inform evidence-based employment policy planning.

8. International Conference on Environment and Climate Dynamics to Be Inaugurated by PM on September 19

Prime Minister Narendra Modi will inaugurate the two-day international conference titled "The Future of Environment and Climate Dynamics" on September 19, 2026, at Vigyan Bhawan, New Delhi. Organized by the National Green Tribunal, the event gathers delegates, judges, and experts from seventeen nations to examine climate challenges, policy execution, and environmental justice. The sessions focus on advancing multi-jurisdictional collaboration, exchanging legal methodologies, and refining institutional frameworks to enforce governance strategies and climate resilience.



मुख्य बिंदु:

- दो दिवसीय सम्मेलन: राष्ट्रीय हरित अधिकरण १९ और २० सितंबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा।
- वैश्विक भागीदारी अपेक्षित: १७ देशों के न्यायाधीशों, पर्यावरण विशेषज्ञों और वरिष्ठ अधिकारियों के जलवायु तथा पर्यावरणीय चुनौतियों पर चर्चा में भाग लेने की उम्मीद है।
- पर्यावरणीय शासन पर ध्यान: सत्रों में जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय शासन, नीतिगत क्रियान्वयन, पर्यावरणीय न्याय और विभिन्न क्षेत्रों के बीच संस्थागत सहयोग की समीक्षा की जाएगी।

9. बिम्सटेक ऊर्जा केंद्र ने उभरती विद्युत क्षेत्र प्रौद्योगिकियों पर पांच दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया

- ✍ बिम्सटेक ऊर्जा केंद्र ने १४ से १८ सितंबर २०२६ तक पांच दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें विद्युत उत्पादन, पारेषण, वितरण और अंतिम उपयोग वाले विद्युत क्षेत्रों में नई तथा उभरती प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रशिक्षण का उद्देश्य क्षेत्रीय ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देना और सदस्य देशों के बीच संस्थागत क्षमताओं को मजबूत करना था। चर्चाओं में स्मार्ट ग्रिड, ग्रिड आधुनिकीकरण, डिजिटल एकीकरण और सतत परिवर्तन के मार्गों पर ध्यान दिया गया, जिससे भाग लेने वाले देशों को साझा तकनीकी ज्ञान के माध्यम से परिचालन बुनियादी ढांचे को उन्नत करने और मजबूत विद्युत प्रणालियां स्थापित करने में सहायता मिली।



मुख्य बिंदु:

- विद्युत क्षेत्र प्रशिक्षण: बिम्सटेक ऊर्जा केंद्र ने विद्युत क्षेत्र को आकार देने वाली उभरती प्रौद्योगिकियों और विकास पर केंद्रित पांच दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया।
- क्षेत्रीय ज्ञान आदान-प्रदान: यह कार्यक्रम भाग लेने वाले बिम्सटेक सदस्य देशों के बीच विकसित हो रही ऊर्जा क्षेत्र की प्रौद्योगिकियों पर तकनीकी सीख और ज्ञान साझा करने को बढ़ावा देता है।
- प्रौद्योगिकी क्षमता निर्माण: उभरती विद्युत प्रौद्योगिकियों पर चर्चा और प्रशिक्षण ऊर्जा क्षेत्र में मजबूत संस्थागत क्षमताओं और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देते हैं।

Key Points:

- Two Day Conference: The National Green Tribunal will host the international conference on September 19 and 20 at Vigyan Bhawan, New Delhi.
- Global Participation Expected: Judges, environmental experts and senior officials from 17 countries are expected to participate in discussions on climate and environmental challenges.
- Environmental Governance Focus: Sessions will examine climate change, environmental governance, policy implementation, environmental justice and institutional cooperation across jurisdictions.

9. BIMSTEC Energy Centre Conducts Five-Day Programme on Emerging Power Sector Technologies

- ✍ The BIMSTEC Energy Centre hosted a five-day capacity building program from fourteen to eighteen September 2026, focusing on new and emerging technologies across generation, transmission, distribution, and end-use power sectors. The training aimed to bolster regional energy cooperation and strengthen institutional capabilities among member states. Discussions centered on smart grids, grid modernization, digital integration, and sustainable transition pathways, enabling participant countries to upgrade operational infrastructure and establish resilient power systems through shared technical knowledge.



Key Points:

- Power Sector Training: The BIMSTEC Energy Centre conducted a five-day programme focused on emerging technologies and developments shaping the power sector.
- Regional Knowledge Exchange: The programme facilitates technical learning and knowledge sharing among participating BIMSTEC member countries on evolving energy-sector technologies.
- Technology Capacity Building: Discussions and training on emerging power technologies support stronger institutional capabilities and regional cooperation in the energy sector.

10. केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर दिल्ली दक्षिण ने २५.२२ करोड़ रुपये से अधिक की इनपुट टैक्स क्रेडिट धोखाधड़ी का खुलासा कर फर्म के मालिक को गिरफ्तार किया

केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर दिल्ली दक्षिण आयुक्तालय की कर चोरी रोधी शाखा ने २५.२२ करोड़ रुपये से अधिक के इनपुट टैक्स क्रेडिट की धोखाधड़ी से प्राप्ति, उपयोग और हस्तांतरण से जुड़े बड़े कर घोटाले का खुलासा किया। जांच में सामने आया कि एक लोहा और इस्पात व्यापारिक फर्म ने बिना किसी वास्तविक माल की आवाजाही के अस्तित्वहीन या निलंबित आपूर्तिकर्ताओं से १४०.१४ करोड़ रुपये मूल्य के फर्जी चालानों का उपयोग किया। फर्म के मालिक को केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, २०१७ की धारा ६९ के तहत गिरफ्तार किया गया और पटियाला हाउस न्यायालय ने उसे १४ दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया।



मुख्य बिंदु:

- फर्जी कर क्रेडिट का पता चला: केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर दिल्ली दक्षिण ने २५.२२ करोड़ रुपये से अधिक के इनपुट टैक्स क्रेडिट की धोखाधड़ी से प्राप्ति, उपयोग और हस्तांतरण का खुलासा किया।
- फर्जी चालानों की जांच: कथित धोखाधड़ी में लगभग १४०.१४ करोड़ रुपये के फर्जी चालान शामिल थे, जिन्हें वास्तविक कारोबारी गतिविधियों से रहित कई आपूर्तिकर्ताओं के माध्यम से जारी किया गया था।
- मालिक को हिरासत में भेजा गया: फर्म के मालिक को केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया और बाद में १४ दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

10. CGST Delhi South Uncovers Over 25.22 Crore Rupees ITC Fraud and Arrests Firm Proprietor

The Anti-Evasion Branch of CGST Delhi South Commissionerate uncovered a major tax fraud involving fraudulent avilment and passing of Input Tax Credit exceeding twenty-five point twenty-two crore rupees. Investigations revealed that an iron and steel trading firm utilized fake invoices worth one hundred forty point fourteen crore rupees from non-existent or suspended suppliers without actual movement of goods. The firm's proprietor was arrested under Section 69 of the CGST Act, 2017 and remanded to judicial custody for fourteen days by Patiala House Court.



Key Points:

- Fraudulent Credit Detected: CGST Delhi South uncovered fraudulent avilment, utilisation and passing of Input Tax Credit exceeding 25.22 crore rupees.
- Bogus Invoices Investigated: The alleged fraud involved bogus invoices worth approximately 140.14 crore rupees issued through multiple suppliers lacking genuine business operations.
- Proprietor Sent To Custody: The firm's proprietor was arrested under the CGST Act and subsequently remanded to judicial custody for 14 days.



दैनिक समसामयिक

DAILY

CURRENT AFFAIRS

MCQs

प्रश्नोत्तरी

Q1. सितंबर २०२६ में केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर दिल्ली दक्षिण ने २५.२२ करोड़ रुपये से अधिक की इनपुट टैक्स क्रेडिट धोखाधड़ी का पता लगाया। वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था के तहत 'आईटीसी' का पूर्ण रूप क्या है?

- (a) आयकर क्रेडिट (b) इनपुट टैक्स क्रेडिट
(c) एकीकृत कर निकासी (d) आयात कर रियायत

Q2. निम्नलिखित में से कौन सा देश बिस्मटेक का सदस्य नहीं है, जिसके ऊर्जा केंद्र ने सितंबर २०२६ में प्रशिक्षण आयोजित किया?

- (a) म्यांमार (b) थाईलैंड
(c) पाकिस्तान (d) भूटान

Q3. २०२६ के उत्तरार्ध में जलवायु सम्मेलनों में उजागर की गई भारत की राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के तहत, शुद्ध-शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए भारत का लक्ष्य वर्ष क्या है?

- (a) २०४० (b) २०५०
(c) २०८० (d) २०७०

Q4. भारत में रोजगार और बेरोजगारी के संकेतकों को मापने के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रमुख आवधिक सर्वेक्षण का नाम क्या है?

- (a) आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS)
(b) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (NSS)
(c) वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (ASI)
(d) उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण (CES)

Q5. सितंबर २०२६ में कड़े अवांछित संदेश नियंत्रण उपायों की घोषणा करने वाले नियामक भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का पूर्ण रूप क्या है?

- (a) भारत का दूरसंचार नियामक संघ
(b) भारत का दूरसंचार नियामक प्राधिकरण
(c) भारत का तकनीकी नियामक प्राधिकरण
(d) दूरसंचार समाधान और विश्लेषण संस्थान

Q1. In September 2026, CGST Delhi South detected an Input Tax Credit (ITC) fraud exceeding 25.22 crore. What does 'ITC' stand for under the GST regime?

- (a) Income Tax Credit
(b) Input Tax Credit
(c) Integrated Tax Clearance
(d) Import Tax Concession

Q2. Which of the following countries is NOT a member of BIMSTEC, whose Energy Centre conducted the training in September 2026?

- (a) Myanmar
(b) Thailand
(c) Pakistan
(d) Bhutan

Q3. Under India's national commitments highlighted at climate conferences in late 2026, what is India's target year to achieve Net-Zero carbon emissions?

- (a) 2040
(b) 2050
(c) 2080
(d) 2070

Q4. What is the name of the flagship periodic survey conducted by MoSPI that measures employment and unemployment indicators in India?

- (a) Periodic Labour Force Survey (PLFS)
(b) National Sample Survey (NSS)
(c) Annual Survey of Industries (ASI)
(d) Consumer Expenditure Survey (CES)

Q5. What is the full form of TRAI, the regulator that announced stringent spam-reduction steps in September 2026?

- (a) Telecommunication Regulatory Association of India
(b) Telecom Regulatory Authority for India
(c) Technical Regulatory Authority of India
(d) Telecom Resolution and Analysis Institute

Q6. सितंबर २०२६ में, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय नौसेना की एनजीएमवी परियोजना के तहत दूसरी पोत के लिए इस्पात काटने का समारोह शुरू किया। 'एनजीएमवी' का पूर्ण रूप क्या है?

- (a) अगली पीढ़ी का समुद्री पोत
- (b) अगली पीढ़ी का मिसाइल पोत
- (c) अगली पीढ़ी का बहुउद्देशीय पोत
- (d) नौसैनिक निर्देशित मिसाइल पोत

Q7. सितंबर २०२६ में भारत और नेपाल के बीच आयोजित द्विपक्षीय व्यापार वार्ता के दौरान, कौन सी खुली सीमा संधि पारंपरिक रूप से दोनों देशों के बीच व्यापार और पारगमन के लिए आधार प्रदान करती है?

- (a) शांति और मैत्री की संधि (१९५०)
- (b) सुगौली की संधि (१८१६)
- (c) भारत-नेपाल व्यापार संधि (१९९१)
- (d) महाकाली संधि (१९९६)

Q8. सितंबर २०२६ में शंघाई सहयोग संगठन के आर्थिक और विदेश व्यापार मंत्रियों की २५वीं बैठक की मेजबानी किस देश ने की?

- (a) उज्बेकिस्तान
- (b) कजाकिस्तान
- (c) ताजिकिस्तान
- (d) किर्गिस्तान

Q9. सितंबर २०२६ में घोषित संशोधन से पहले थोक उपभोक्ताओं के लिए चीनी भंडारण की सीमा कितने दिनों की थी?

- (a) ७ दिन
- (b) २५ दिन
- (c) २० दिन
- (d) १५ दिन

Q10. सितंबर २०२६ में घोषित अनुसार, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत ३० लाख कारीगर पंजीकृत हुए। इस योजना को लागू करने वाला नोडल केंद्रीय मंत्रालय कौन सा है?

- (a) ग्रामीण विकास मंत्रालय
- (b) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
- (c) कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय
- (d) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

Q6. In September 2026, Cochin Shipyard Limited (CSL) initiated the steel-cutting ceremony for the second vessel under the Indian Navy's NGMV project. What does 'NGMV' stand for?

- (a) Next Generation Maritime Vessel
- (b) Next Generation Missile Vessel
- (c) Next Generation Multipurpose Vessel
- (d) Naval Guided Missile Vessel

Q7. During the bilateral trade talks held in September 2026 between India and Nepal, which open border treaty traditionally forms the framework for trade and transit between the two nations?

- (a) Treaty of Peace and Friendship (1950)
- (b) Treaty of Sagauli (1816)
- (c) Indo-Nepal Trade Treaty of 1991
- (d) Mahakali Treaty (1996)

Q8. Which country hosted the 25th Meeting of the Shanghai Cooperation Organisation (SCO) Economic and Foreign Trade Ministers in September 2026?

- (a) Uzbekistan
- (b) Kazakhstan
- (c) Tajikistan
- (d) Kyrgyzstan

Q9. What was the earlier sugar stockholding limit for bulk consumers prior to the revision announced in September 2026?

- (a) 7 days
- (b) 25 days
- (c) 20 days
- (d) 15 days

Q10. As announced in September 2026, 30 lakh artisans registered under the PM Vishwakarma scheme. Which Union Ministry is the nodal agency implementing this scheme?

- (a) Ministry of Rural Development
- (b) Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises
- (c) Ministry of Skill Development and Entrepreneurship
- (d) Ministry of Commerce and Industry

उत्तरमाला (Answer Key)

- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| 1 | B | 2 | C | 3 | D | 4 | A | 5 | B | 6 | B | 7 | A | 8 | C | 9 | D | 10 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|

